

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 108/18 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.3 मुख्यालय बज्जु।

—प्रार्थी

: ब न अ म :

हरुराम पुत्र तुलछाराम जाट सा. भागूमील करवास तह. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

—अप्रार्थी

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ।
2. अप्रार्थी हाजिर नहीं।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975



: आदेश :

दिनांक 11.09.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.12.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय को हस्तान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.2 के चक 9 एमआरएम(ए) के मु.नं. 09/20 की 18.19 बीघा कमाण्ड व 4.11 बीघा अनकमाण्ड कुल 23.10 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2007 को राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटित की गयी जो नियम विरुद्ध होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गयी।
3. अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर विभागीय प्रतिनिधि की एकतरफा बहस सुनी गयी।
4. प्रार्थी स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को विनियम समिति की अनुशंसा के बिना आवंटन अधिकारी द्वारा विनियम में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि प्रकरण विनियम कमेटी में सक्षम नहीं है। लॉटरी पर्ची नहीं है। पेन्डिंग जांच में खातेदारी जारी की गयी है। इससे यह प्रकट होता है कि आवंटन में घोर अनियमितता की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 22(3) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नियम विरुद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमिआवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम प्रकरण में विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते हैं।
6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.2 के चक 9 एमआरएम(ए) के मु.नं. 09/20 की 18.19 बीघा कमाण्ड व 4.11 बीघा अनकमाण्ड कुल 23.10 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित निर्णय पारित करें।
7. आदेश आज दिनांक 11.09.19 को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कुमार पाल गौतम)
जिला कलेक्टर, बीकानेर
जिला कलेक्टर, बीकानेर